

अर्थव्यवस्था · Economy

RBI का ₹50,000 करोड़ का VRR ऑक्शन, भारत-पोलैंड व्यापार समझौता और सामाजिक सहायता योजना

आरबीआई द्वारा तरलता प्रबंधन हेतु ₹50,000 करोड़ का VRR ऑक्शन, भारत-पोलैंड व्यापार 2030 तक दोगुना करने का लक्ष्य और ₹53,428 करोड़ की सामाजिक सहायता योजना को मंजूरी।

अर्थव्यवस्था · Economy

1. RBI की ₹50,000 Cr की VRR नीलामी

- बैंकिंग प्रणाली में तरलता बढ़ाने हेतु 3-दिवसीय VRR आयोजित
- ₹33,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों की हामीदारी संपन्न
- अल्पकालिक ब्याज दरों में स्थिरता बनाए रखना मुख्य उद्देश्य

अर्थव्यवस्था · Economy

2. भारत-पोलैंड आर्थिक साझेदारी

- 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का साझा लक्ष्य
- पोलिश पीएम डोनाल्ड टस्क की उच्चस्तरीय भारत यात्रा
- विनिर्माण, रक्षा व खाद्य प्रसंस्करण में निवेश को प्रोत्साहन

अर्थव्यवस्था · Economy

3. PM सामाजिक सहायता योजना

- ₹53,428 करोड़ के परिव्यय से NSAP का पुनर्गठन
- दिव्यांगता पेंशन हेतु सीमा 80% से घटाकर 40% की गई
- 18 वर्ष की आयु सीमा समाप्त, जन्म से ही पेंशन की पात्रता

परीक्षा के लिए तथ्य · Facts for Exams

याद रखें

Remember

VRR नीलामी अधिसूचित राशि	₹50,000 करोड़
-----------------------------	---------------

G-Sec हमीदारी नीलामी आकार	₹33,000 करोड़
------------------------------	---------------

भारत-पोलैंड व्यापार दोगुना करने का वर्ष	2030
--	------

प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना अवधि	2026-27 से 2030-31 (5 वर्ष)
---	-----------------------------

सामाजिक सहायता योजना कुल परिव्यय	₹53,428 करोड़
-------------------------------------	---------------

संशोधित दिव्यांगता पेंशन बेंचमार्क	40% (RPwD अधिनियम 2016 अनुसार)
---------------------------------------	-----------------------------------

अभ्यास प्रश्न · Practice MCQ

बैंकिंग प्रणाली में अल्पकालिक तरलता (Liquidity Injection) बढ़ाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा निम्नलिखित में से किस साधन का उपयोग किया जाता है?

- A परिवर्तनीय दर रेपो (VRR)
- B परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (VRRR)
- C नकद आरक्षित अनुपात (CRR) में वृद्धि
- D सांविधिक तरलता अनुपात (SLR) में वृद्धि

उत्तर / Answer: A — आरबीआई बाजार में तरलता डालने के लिए वेरिएबल रेट रेपो (VRR) और तरलता सोखने के लिए वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो (VRRR) का संचालन करता है।

अभ्यास प्रश्न · Practice MCQ

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पुनर्गठित 'प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना' (पूर्ववर्ती NSAP) के लिए 2026-27 से 2030-31 तक कितनी राशि का परिव्यय स्वीकृत किया गया है?

A ₹53,428 करोड़

B ₹45,200 करोड़

C ₹62,500 करोड़

D ₹38,750 करोड़

उत्तर / Answer: A — केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों के लिए ₹53,428 करोड़ के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना के रूप में मंजूरी दी है।

पूरा लेख, PDF और रोज़ के अपडेट

Full article, PDF & daily updates

हिंदी और English दोनों में पढ़ें

aajkagk.com

पेज को **Follow** करें और **Share** करें

Follow the page & share with friends